धूपा चमार और अन्य

बनाम

बिहार राज्य

[उमेश सी. बनर्जी और बी.एन. अग्रवाल, जे.जे.]

अकेले चोट पहुंचाकर हत्या - धारा 300 का खंड तीसरा--। की प्रयोज्यता-धारण किया गया, अभियुक्त ने जानबूझकर निशाना साधा और चोट पहुंचाई। मृतक के सीने में घातक हथियारों के साथ पर्याप्त बल लगाया गया मृत्यु - मेडिकल रिपोर्ट से पुष्टि - साक्ष्य का अभाव या उचित, उसी का खंडन करने के लिए स्पष्टीकरण-परिस्थितियों के तहत, यह अनुमान लगाया जा सकता है कि मृतक को पहुंचाई गई ऐसी एक अकेली चोट ही पर्याप्त है। मौत का कारण बनने के लिए प्रकृति का सामान्य कोर्स-खंड तीसरा, धारा 300 आकर्षित होती है।

गैरकानूनी सभा-गठन-आयोजित, जब सात में से तीन अभियुक्तों को आरोप से बरी कर दिया गया और किसी अन्य व्यक्ति ने इसमें भाग नहीं लिया अपराध, कोई गैरकानूनी सभा नहीं हो सकती-इसलिए धारा के तहत सजा 302/149 अनुचित हो जाता है।

अभियोजन पक्ष के मुताबिक मारपीट की घटना हुई थी। मुखबिर के बेटे और अपीलकर्ता नंबर 2 के बीच। फिर अगले दिन, अपीलकर्ता-

अभियुक्त (सात की संख्या में) भाला, लाठियों और हथियारों से लैस ईंट-पत्थर चलाने वाले मुखबिर के घर के पास जमा हो गए और परिवार के साथ दुर्व्यवहार किया सदस्यों ने सूचक, उसके बेटे और ग्रामीणों पीडब्ल्यू 6, पीडब्ल्यू 4, पीडब्ल्यू3, पीडब्ल्यू2 और उसकी बहू वहां पहुंचे और जब उनके विरोध करने पर अपीलार्थी क्रमांक एक ने बहू की गर्दन पर भड़ास से वार कर दिया, पीडब्ल्यु 2 वहीं गिर पड़ी और तुरंत मर गई; आरोपियों में से एक सूचक के पुत्र को मारपीट कर घायल कर दिया; एक और आरोपी को सज़ा पीडब्ल्यु6 को भाला झटका, और फिर भी एक अन्य आरोपी ने भाला को चोट पहुंचाई। सूचक के पेट पर और तीन अन्य आरोपियों ने ईंट-पत्थर से हमला किया।

अभियोजन पक्ष के अन्य गवाह वहां मौजूद थे। घायल व्यक्ति को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सूचक के बेटे को मृत घोषित कर दिया गया। उसकी मां ने एफआईआर दर्ज करायी, पुलिस ने सभी के विरुद्ध आरोप पत्र समर्पित किया। आरोपी व्यक्ति. विचारण न्यायालय ने दो आरोपियों को धाराओं के तहत दोषी ठहराया।

अन्य दो आरोपियों को धारा 302 और 148 आईपीसी के तहत दोषी ठहराया गया एवं धारा 149, 148 एवं 323 आईपीसी में शेष तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया।

विचारण न्यायालय ने अपील पर उच्च न्यायालय की दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की। अपीलकर्ता संख्या 2 की दोषसिद्धि में संशोधन के साथ सभी अभियुक्तों की धारा 302 के तहत है, इसलिए यह चारों दोषी अभियुक्तों द्वारा अपील।

अपीलकर्ताओं की ओर से यह तर्क दिया गया कि अपीलकर्ता संख्या की दोषसिद्धि में अनुचित था, क्योंकि उसने मृतक को एक ही वार किया था, आईपीसी की धारा 300 का खंड तीसरा लागू नहीं होगा; वह सात में से अभियुक्तों में से तीन को आईपीसी की धारा 302/149 के तहत आरोप से बरी कर दिया गया और इसलिए, आईपीसी की धारा 302/149 के तहत आरोपी व्यक्तियों को दोषी ठहराया गया उचित नहीं था, क्योंकि ये अभियुक्त पहले ही इससे अधिक सजा काट चुके थे। आईपीसी की अन्य धाराओं के तहत अधिकतम सज़ा, और होनी भी चाहिए तुरंत जारी किया गया.

अपीलकर्ताओं 2 से 4 की अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए खारिज करते हुए न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया

1. न्यायालय की अपील तत्काल मामले के तथ्यों की जांच करने पर, अर्थात मामला सुलझा लिया गया। कानून के सिद्धांत, आईपीसी की धारा 300 का खंड तीसरा पूरी तरह से आकर्षित होता है। यह ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी व्यक्ति घातक हथियारों से लैस होकर आए थे। इसके

बाद अपीलकर्ता के साथ बहस हुई और गरम शब्दों का आदान-प्रदान हुआ नहीं, मैंने पीड़ित/मृतक पर भाला से हमला किया, जिससे उसकी छाती पर चोट आई, महत्वपूर्ण रक्त वाहिकाओं को तोड़ना और महाधमनी और अन्य धमनियों को काटना जिसके परिणामस्वरूप उसकी तत्काल मृत्यु हो गई। चोट की प्रकृति को देखते हुए जिससे महाधमनी और धमनियों में महत्वपूर्ण रक्त वाहिकाएं फट गईं काट दिए गए और जब डॉक्टर ने राय दी तो मौत इसी के कारण हुई बड़ी नसों के फटने के कारण गंभीर रक्तस्राव और सदमा, निःसंदेह, इससे उचित रूप से यह अनुमान लगाया जा सकता है कि ऐसा एकान्त मृतक को पहुंचाई गई चोट मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी प्रकृति का सामान्य क्रम. (424-बी, एफ]

विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1958 एससी 465; जगरूप सिंह बनाम द हरियाणा राज्य, एआईआर (1981) एससी 1552; गुदर दुसाध बनाम बिहार राज्य, एआईआर 1972 एससी 952; जय प्रकाश बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), (1991] 2 एससीसी 32; कर्नाटक राज्य बनाम वेदनायगम, (1995)I एससीसी 326 और महेश बाल्मीकि उर्फ मुन्ना बनाम मध्य प्रदेश राज्य, (2000] (1) एससीसी 319, पर भरोसा किया गया।

2. परिस्थिति यह दर्शाएगी कि अभियुक्त ने जानबूझ कर चोट पहुंचाई और वही मन की ऐसी स्थिति का संकेत देगी। अपीलकर्ता नंबर 1, कि उसने घातक हथियार से निशाना बनाकर चोट पहुंचाई। यह दिखाने के

लिए साक्ष्य या उचित स्पष्टीकरण के अभाव में अपीलकर्ता का इरादा सीने में चोट पहुंचाने का नहीं था महत्वपूर्ण रक्त वाहिका को तोड़ने और काटने के लिए पर्याप्त बल की डिग्री महाधमनी और अन्य धमनियों के मामले में, यह निष्कर्ष निकालना विकृत होगा कि उसने ऐसा किया वह चोट पहुँचाने का इरादा नहीं था जो उसने किया। एक बार घटक 'इरादा' स्थापित हो जाता है तो इच्छित चोट के रूप में अपराध हत्या होगी। प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त था। इसलिए, अपरिहार्य निष्कर्ष यह होगा कि अपीलकर्ता नंबर । ने अपराध किया है। हत्या का अपराध और गैर इरादतन हत्या का अपराध। यह स्थिति होने के कारण, उच्च न्यायालय ने कोई त्रुटि नहीं की है दंड की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता संख्या । की दोषसिद्धि को बरकरार रखना कोड. [424-जी, एच; 425-ए, बी.जे]

3. चूँकि सात अभियुक्तों में से तीन अभियुक्त व्यक्ति थे। विचारण न्यायालय ने ही आईपीसी की धारा 302/149 के तहत आरोप से बरी कर दिया और जैसा कि उल्लेख किया गया है कि किसी अन्य व्यक्ति के अपराध में शामिल होने की बात नहीं कही गई है। अभियोजन मामले और साक्ष्य में, और आरोपी व्यक्तियों की संख्या के रूप में पाँच से कम हो जाने पर यह नहीं कहा जा सकता कि वहाँ कोई गैरकानूनी जमावड़ा है। इस प्रकार अपीलकर्ता संख्या 2 से 4 को धारा 302/आई 49 के तहत दोषी

ठहराया गया गैरकानूनी जमावड़े के कारण मुखबिर के बेटे की मृत्यु हो जाती है, अनुचित।

अभियुक्त-अपीलकर्ता संख्या 2, 3 और को दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई तथा अभियुक्त 4 को दंड संहिता की धारा 302/l49 के तहत अलग रखा गया है और इस आरोप से बरी कर दिया गया। हालाँकि, उनकी दोषसिद्धि और सजाएँ नीचे हैं अन्य अनुभागों की पुष्टि की जाती है। [425-ई, एफ; 426-ए, बी.जे

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या. 1087/ 200

पटना उच्च न्यायालय के आपराधिक याचिका सं. 480/ 1987 निर्णय एवं आदेश दिनांक 28.4.2000 से

अमन लेखी, राजेश पाठक, प्रमोद जालान और एस.आर. सेतिया, के लिए अपीलकर्ता।

प्रतिवादी की ओर से साकेत सिंह और बी.बी. सिंह।

न्यायालय का निर्णय बी.एन. अग्रवाल, जे. सुनाया गया।

धूपा चमार-अपीलकर्ता संख्या 1 और तोखा चमार-अपीलकर्ता नंबर 2 को विचारण न्यायालय ने धारा 302 के तहत दोषी ठहराया था। दंड संहिता के तहत आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। उनमें से प्रत्येक को दंड

संहिता की धारा 148 के तहत दोषी ठहराया गया और सजा सुनाई गई, एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा। धूपा चमार-अपीलकर्ता नंबर 1 और तोखा चमार-अपीलकर्ता नंबर 2 को निचली अदालत ने दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उनमें से प्रत्येक को दंड संहिता की धारा 148 के तहत दोषी ठहराया गया और एक वर्ष के लिए कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। डोमा चमार-अपीलकर्ता नंबर 3 और अदालत चमार-अपीलकर्ता नंबर 4 को दंड संहिता की धारा 302/149 के तहत दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई।उन्हें दंड संहिता की धारा 148 और 323 के तहत दोषी ठहराया गया और क्रमशः एक वर्ष और छह महीने के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। सजाएँ एक साथ चलने का आदेश दिया गया था। अभियुक्त स्वामीनाथ चमार, राजबली चमार और राम होशियार चमार, जिन पर दंड संहिता की धारा 302/149 के तहत आरोप लगाए गए थे, को विचारण न्यायालय ने उक्त आरोपों से बरी कर दिया था। अपीलकर्ताओं की अपील पर उच्च न्यायालय ने केवल इस संशोधन के साथ उनकी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की कि तोखा चमार-अपीलकर्ता नंबर 2 की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को दंड संहिता की धारा 302/149 के तहत एक में बदल दिया गया था।

अभियोजन का मामला, संक्षेप में यह है कि 13 जून, 1983 को रात 8 बजे संकेशिया देवी (सूचनाकर्ता) के बेटे रामू चमार और अपीलकर्ता नंबर

2-तोखा चमार के बीच मुक्कों और थप्पड़ों से मारपीट की घटना हुई थी और इसके कारण कारण 14 जून 1983 को सुबह 8 बजे, अपीलकर्ता भालों से लैस होकर अभियुक्त राम होशियार चमार पर लाठी से हमला किया और स्वामीनाथ चमार और राजबली चमार पर ईंट-पत्थर लेकर हमला किया और रामू चमार के घर के पास आए और उनके परिवार के सदस्यों को गाली देना शुरू कर दिया, जिसके बाद ग्रामीण खेदारू चमार (पीडब्ल्यूयू) 4), झगरू चमार (पीडब्ल्यू 3), परिवादी का बेटा धरम चमार (मृतक), करम चमार (पीडब्ल्यू 2) और उसकी बहू, राम पतिया देवी, के अलावा शारदा देवी (पीडब्ल्यू 6) वहां पहुंचे। राम पतिया देवी ने विरोध किया, जिस पर अपीलकर्ता नंबर 1- धूपा चमार ने उसकी गर्दन के बाईं ओर एक भाला मारा और उसे गर्दन से जबरन खींच लिया, जिसके परिणामस्वरूप वह गिर गई और तुरंत मर गई। अपीलकर्ता क्रमांक 2-तोखा चमार ने धरम चमार के पेट में भाला से हमला किया। अपीलकर्ता संख्या 4-अदालत चमार ने शारदा देवी (पीडब्ल्यू 6) को भाला चोट पहुंचाई। आरोपी राजबली चमार और स्वामीनाथ चमार ने करम चमार (पीडब्ल्यू 2) पर ईंट-पत्थर फेंके। आरोपी राम होशियार चमार ने रामू को लाठी से वार कर दिया. अपीलकर्ता संख्या 3-डोमा चमार ने अभियुक्तों की हरकत का विरोध करने पर सूचक के पेट में भल्ला मार दिया, जिसके परिणामस्वरूप वह गिर गई और उसके बाद घायल धरम चमार और शारदा देवी (पीडब्ल्यूयू 6) को अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल जहां धरम चमार को मृत घोषित कर दिया गया। उपरोक्त तथ्यों को बताते हुए पुलिस

द्वारा उसी दिन सुबह 11 बजे घटना स्थल पर ही संकेशिया देवी का फर्द बयान दर्ज किया गया, जिसके आधार पर औपचारिक प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की गयी।

पुलिस ने जांच शुरू की और उसके पूरा होने पर आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिसके प्राप्त होने पर संज्ञान लिया गया और अपीलकर्ताओं सहित सभी सात आरोपियों को मुकदमे का सामना करने के लिए सत्र अदालत में पेश किया गया। अभियुक्तों ने निवेदन किया कि वे निर्दोष हैं और जो घटना कथित तौर पर घटित हुई है, उसके अलावा कोई घटना घटित नहीं हुई है।

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने बारह गवाहों से पूछताछ की। पीडब्ल्यू 1 से 7 ने परिवादी (पीडब्ल्यू 11) के अलावा घटना के चश्मदीद गवाह होने का दावा किया, पीडब्ल्यू 8 और 10 औपचारिक गवाह हैं, पीडब्ल्यू9 को प्रस्तुत किया गया था और पीडब्ल्यू-12 ने डॉक्टर के रूप में चिकित्सा साक्ष्य साबित किया है, जिसने पोस्टमॉर्टम परीक्षण किया था।

जांच अधिकारी से अदालत गवाह नंबर 1 के रूप में पूछताछ की गई।हालाँकि, बचाव पक्ष ने तीन गवाहों से पूछताछ की। मुकदमे के समापन पर, विद्वान सत्र न्यायाधीश ने उपरोक्त उल्लिखित तीन आरोपियों को दंड संहिता की धारा 302/149 के तहत आरोप से बरी करते हुए, अपीलकर्ताओं को ऊपर बताए अनुसार दोषी ठहराया।

अपील किए जाने पर, उच्च न्यायालय द्वारा दोषसिद्धि और सजा को केवल इस संशोधन के साथ बरकरार रखा गया है कि धारा 302 के तहत अपीलकर्ता संख्या 2-तोखा चमार की दोषसिद्धि को दंड संहिता की धारा 302/149 के तहत बदल दिया गया है।

अत: यह अपील विशेष अनुमति द्वारा।

अपील के समर्थन में अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री अमन लेखी, निचली नीचे दी गई दो अदालतों द्वारा दर्ज किए गए तथ्य के समवर्ती निष्कर्षों पर सफलतापूर्वक विरोध नहीं कर सके क्योंकि पार्टियों की ओर से पेश किए गए सबूतों की सराहना के बाद ये निष्कर्ष निकाले गए थे।

हालाँकि, उन्होंने अभिकथित किया कि दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता नंबर 1-धूप चमार की दोषसिद्धि अनुचित थी और जैसा कि कहा गया है कि उसने मृतक राम पतिया देवी को एक ही आद्यात दिया था, दंड संहिता की धारा 300 का खंड तीसरा आकर्षित नहीं किया जाएगा और, तदनुसार, अपीलकर्ता-धूपा चमार का कृत्य हत्या की श्रेणी में नहीं आएगा।

इस प्रकार, एक प्रश्न उठता है कि जब मृत्यु एक ही आद्यात से होती है, तो क्या दंड संहिता की धारा 300 का खंड तीसरा आकर्षित होता है।

उस खंड में घटक आशय बहुत महत्वपूर्ण है और यह किसी दिए गए मामले में एक सुराग देता है कि इसमें शामिल अपराध हत्या है या नहीं।

दंड संहिता की धारा 300 का खंड तीसरा इस प्रकार है: - "तीसरा। यदि यह किसी व्यक्ति को शारीरिक चोट पहुंचाने के इरादे से किया जाता है और पहुंचाई जाने वाली शारीरिक चोट प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है,

आशय मकसद से अलग है। यह आशय ही है जिसके साथ कार्य किया जाता है, जिससे इस निष्कर्ष पर पहुंचने में फर्क पड़ता है कि अपराध गैर इरादतन हत्या है या हत्या।

इसलिए, इन प्रावधानों में प्रयुक्त अभिव्यक्ति आशय का अर्थ जानना आवश्यक है। इस संबंध में, हम विवियन बोस, जे. के उच्च प्राधिकारी का उल्लेख उपयोगी रूप से कर सकते हैं, जिनके साथ जाफ़र इमाम और पी.बी.गजेंद्रगडकर, जे.जे. विरसा सिंह बनाम पंजाब राज्य एआईआर 1958 एससी 465 के मामले में सहमति व्यक्त की गई। उस मामले में, अपीलकर्ता विरसा सिंह को दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया गया था, जिसे इस न्यायालय ने बरकरार रखा था, हालांकि केवल एक चोट थी जिसके लिए उसे जिम्मेदार ठहराया गया था। जो भाले के प्रहार के परिणामस्वरूप हुआ था।

उस मामले में यह तर्क दिया गया था कि चूंकि यह एकमात्र चोट का मामला था, इसलिए यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता था कि शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा था जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त था। इस प्रकार अपराधी का ऐसा कृत्य हत्या के बराबर नहीं था। खंड तीसरे का विश्लेषण करने के बाद, इसे उस मामले में निर्धारित किया गया था जहां विवियन बोस, जे. ने न्यायालय के लिए बोलते हुए, पृष्ठ 467 पर इस प्रकार कहा: -

> "इसे संक्षेप में कहें तो, अभियोजन पक्ष को धारा 300 के तीसरे खंड के तहत मामला लाने से पहले निम्नलिखित तथ्यों को साबित करना होगा "तीसरा"; सबसे पहले, इसे काफी निष्पक्ष रूप से स्थापित करना होगा, कि शारीरिक चोट मौजूद है;
>
> दूसरे, चोट की प्रकृति सिद्ध होनी चाहिए; ये पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ जांच हैं।
>
> तीसरा, यह साबित किया जाना चाहिए कि उस विशेष शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा था, यानी यह आकस्मिक या अनजाने में नहीं था, या किसी अन्य प्रकार की चोट का इरादा था। एक बार जब ये तीन तत्व मौजूद साबित हो जाते हैं, तो जांच आगे बढ़ जाती है, और चौथा, यह साबित

होना चाहिए कि ऊपर बताए गए तीन तत्वों से बनी जिस प्रकार की चोट का वर्णन किया गया है, वह प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है।

जांच का यह हिस्सा पूरी तरह से वस्तुनिष्ठ और अनुमानात्मक है और इसका अपराधी के इरादे से कोई लेना-देना नहीं है।

एक बार जब ये चार तत्व अभियोजन पक्ष द्वारा स्थापित कर दिए जाते हैं (और, निश्चित रूप से, सारा बोझ अभियोजन पर होता है) तो अपराध धारा 300 के तीसरे खंड के तहत हत्या है,

इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऐसी चोट पहुँचाने का कोई इरादा नहीं था जो प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त हो (ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच कोई वास्तविक अंतर है)। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि उस तरह के कृत्य से मृत्यु होने की संभावना होगी।

एक बार पीडित पर शारीरिक चोट पहुंचाने का इरादा वास्तव में मौजूद पाया जाता है, तो साबित हो जाता है, बाकी जांच पूरी तरह से वस्तुनिष्ट होती है और एकमात्र

सवाल यह है कि क्या, वस्तुनिष्ट रूप से उद्देश्यपूर्ण अनुमान के मामले में, चोट प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिये पर्याप्त है। किसी के पास ऐसी चोटें पहुंचाने का लाइसेंस नहीं है जो प्रकृति की सामान्य प्रक्रिया में मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त हों और फिर यह दावा करें कि वे हत्या के दोषी नहीं हैं। यदि वे उस प्रकार की चोटें पहुंचाते हैं, तो उन्हें परिणाम भुगतने होंगे; और वे केवल तभी बच सकते हैं जब यह दिखाया जा सके, या उचित रूप से यह निष्कर्ष निकाला जा सके कि चोट आकस्मिक थी या अन्यथा अनजाने में हुई थी।"

पृष्ठ 468 पर अभिकथित किया गया कि :-

"सबूतों या उचित स्पष्टीकरण के अभाव में, कि कैदी का पेट में इतनी ताकत से वार करने का इरादा नहीं था कि शरीर में इतनी दूर तक घुस सके, या यह संकेत दे सके कि उसका कृत्य एक खेदजनक दुर्घटना थी और उसका इरादा अन्यथा था, यह निष्कर्ष निकालना गलत होगा कि उसने जो चोट पहुंचाई उसका इरादा चोट पहुंचाने का नहीं था।"

एक बार जब वह इरादा स्थापित हो जाता है (और इस मामले में कोई अन्य निष्कर्ष उचित रूप से संभव नहीं है और किसी भी मामले में

यह तथ्य का प्रश्न है), तो बाकी चोट की प्रकृति और गंभीरता के बारे में चिकित्सा और अन्य सबूतों से वस्तुनिष्ट निर्धारण का मामला है।

इसे इस प्रकार उसी पृष्ठ पर कहा गया :-

> "सवाल यह नहीं है कि कैदी का इरादा गंभीर चोट पहुंचाने का था या मामूली चोट पहुंचाने का, बल्कि सवाल यह है कि क्या उसका इरादा ऐसी चोट पहुंचाने का था जो साबित हो चुकी है। यदि वह दिखा सकता है कि उसने ऐसा नहीं किया, या यदि परिस्थितियों की समग्रता इस तरह के अनुमान को उचित ठहराती है, तो निश्चित रूप से धारा के लिए आवश्यक आशय साबित नहीं होता है। लेकिन अगर चोट और इस तथ्य से परे कुछ भी नहीं है कि अपीलकर्ता ने इसे पहुंचाया है, तो एकमात्र संभावित निष्कर्ष यह है कि वह इसे पहुंचाना चाहता था। क्या उसे इसकी गंभीरता के बारे में पता था, या उसके गंभीर परिणामों का इरादा था, यह अप्रांसगिक है।"

जहां तक इरादे का सवाल है, सवाल यह नहीं है कि क्या उसका इरादा हत्या करना था, या किसी विशेष डिग्री की गंभीर चोट पहुंचाना था, बल्कि यह है कि क्या उसका इरादा संबंधित चोट पहुंचाने का था; और एक बार चोट का अस्तित्व साबित हो जाने पर इसे कारित करने का इरादा

मान लिया जाएगा, जब तक कि सबूत या परिस्थितियाँ विपरीत निष्कर्ष की गारंटी न दें।

लेकिन इरादा है या नहीं, यह तथ्य का विषय है, कानून का नहीं। क्या घाव गंभीर है या अन्यथा, और यदि गंभीर है, तो कितना गंभीर है, यह एक पूरी तरह से अलग और विशिष्ट प्रश्न है और इसका इस सवाल से कोई लेना-देना नहीं है कि क्या कैदी का इरादा चोट पहुंचाने का था।

यह सच है कि किसी दिए गए मामले में जांच चोट की गंभीरता से जुड़ी हो सकती है। उदाहरण के लिए, यदि यह साबित किया जा सकता है, या यदि परिस्थितियों की समग्रता एक अनुमान को उचित ठहराती है, कि कैदी ने केवल सतही खरोंच का इरादा किया था और दुर्घटनावश उसका शिकार लड़खड़ा गया और इस्तेमाल की गई तलवार या भाले पर गिर गया, तो निश्चित रूप से अपराध हत्या नहीं है।

लेकिन ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि कैदी का आशय उतना गंभीर उस चोट को पहुंचाने का नहीं था जो वह पहुंचाना चाहता था, लेकिन यह इतनी गंभीर हो गई, बल्कि इसलिए कि उसका आशय चोट पहुंचाने का बिल्कुल भी नहीं था। ऐसे में उसका इरादा बिल्कुल अलग तरह की चोट पहुंचाने का होगा।

अंतर कानून का नहीं बल्कि तथ्य का है; और क्या निष्कर्ष एक तरह से या दूसरे तरीके से होना चाहिए, यह सबूत का मामला है, जहां

आवश्यक हो, प्रत्यक्ष गवाही के अभाव में तथ्य के सभी उचित निष्कर्षों की सहायता लेकर यह अनुमान लगाने और काल्पनिक अनुमान लगाने वाला नहीं है।

इन टिप्पणियों का उल्लेख करते हुए, जगरूप सिंह बनाम हरियाणा राज्य, एआईआर 1981 एससी 1552 के मामले में इस न्यायालय की एक खंडपीठ ने पृष्ठ 1552 पर इस प्रकार टिप्पणी की: -

> "विवियन बोस, जे. की ये टिप्पणियाँ लोकस क्लासिकस बन गई हैं।
>
> विरसा सिंह के मामले में क्लॉज थर्ड की प्रयोज्यता के लिए निर्धारित परीक्षण अब हमारी कानूनी प्रणाली में शामिल हो गया है और कानून के शासन का हिस्सा बन गया है।
>
> विरसा सिंह के मामले में निर्णय को मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में अपनाया गया है।"

गुदर दुसाध बनाम बिहार राज्य, एआईआर 1972 एससी 952 के मामले में, सिर पर एक लाठी मारी गई जो घातक साबित हुई। दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कानून प्रतिपादित किया और न्यायालय के लिए बोलते हुए, एच.आर.खन्ना, जे. ने पृष्ठ 954 पर इस प्रकार कहा: -

"तथ्य यह है कि अपीलकर्ता ने सिर पर केवल एक ही वार किया, इससे अपीलकर्ता का अपराध कम नहीं होगा और उसे गैर इरादतन हत्या के अपराध का दोषी नहीं ठहराया जा सकेगा।

रामलाल के सिर पर लाठी का वार स्पष्ट रूप से कुछ बल के साथ किया गया था और इसके परिणामस्वरूप बायीं पार्श्विका की हड्डी में 3" लंबा फ्रैक्चर हो गया।

रामलाल की तत्काल मृत्यु हो गई और इस प्रकार, उसे दूसरा आधात देने का कोई अवसर नहीं आया।

चूंकि सिर पर चोट जानबूझकर कारित की गई थी और आकस्मिक नहीं थी और चूंकि चोट प्रकृति के सामान्य क्रम में मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी, इसलिए अपीलकर्ता के खिलाफ मामला पूरी तरह से भारतीय दंड संहिता की धारा 300 के खंड "तीसरे" के दायरे में आएगा।

जय प्रकाश बनाम राज्य (दिल्ली प्रशासन), (1991) 2 एससीसी 32 के मामले में, जो भी इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ का निर्णय है, चाकू से छाती पर एक ही वार किया गया और वही घातक साबित हुआ। इस प्रकार दंड संहिता की धारा 302 के तहत इस तरह दोषसिद्धि को इस न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था।

न्यायालय ने धारा 300 के खण्ड तीसरे पर विचार करते हुए पृष्ठ 41-42 पर इस प्रकार टिप्पणी की:-

खंड तीसरे में दो भाग हैं। पहला भाग यह है कि वह चोट पहुंचाने का इरादा था जो मौजूद पाई गई और दूसरा भाग यह है कि उक्त चोट प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त है।

पहले भाग के तहत अभियोजन पक्ष को दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों से यह साबित करना होगा कि अभियुक्त का इरादा उस विशेष चोट को कारित करना था।

जबकि दूसरा भाग कि क्या यह मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त था, एक वस्तुनिष्ठ जांच है और यह चोट के विवरण से अनुमान या कटौती का मामला है।

धारा 300 के खंड तीसरे की भाषा दो स्थानों पर इरादे की बात करती है और प्रत्येक में अभियोजन पक्ष द्वारा उस खंड में मामला आने से पहले अनुक्रम स्थापित करना होता है।

अभियुक्तों का 'इरादा' और 'ज्ञान' व्यक्तिपरक और अदृश्य मन की अवस्थाएं हैं और उनके अस्तित्व को परिस्थितियों से इकट्ठा किया जाना चाहिए, जैसे कि इस्तेमाल किए गए हथियार, हमले की क्रूरता, चोटों की बहुलता और अन्य सभी आसपास की परिस्थितियां।

संहिता के निर्माताओं ने जानबूझकर 'आशय' और जानकारी शब्दों का उपयोग किया है और यह स्वीकृत है कि किसी कार्य को करने के

परिणामस्वरूप होने वाले परिणामों की जानकारी उन परिणामों को कारित करने के आशय के समान नहीं है।

सबसे पहले, जब कोई कार्य किसी व्यक्ति द्वारा किया जाता है, तो यह माना जाता है कि उसे पता होना चाहिए कि कुछ निर्दिष्ट हानिकारक परिणाम होंगे या हो सकते हैं। लेकिन वह जानकारी महज जागरूकता है और इरादे के समान नहीं है कि ऐसे परिणाम सामने आएं।

जानकारी की तुलना में, 'इरादे' के लिए परिणामों की कल्पना मात्र से कुछ अधिक की आवश्यकता होती है, अर्थात् किसी विशेष लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उद्देश्यपूर्ण ढंग से कार्य करना।"

[जोर दिया गया] न्यायालय ने पृष्ठ 42-43 पर आगे कहा:-

इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि 'इरादे' के विपरीत जानकारी कुछ तथ्यों के प्रति सचेत जागरूकता की नग्न अवस्था के साथ मानसिक बोध की स्थिति को दर्शाता है जिसमें मानव मन लापरवाह या निष्क्रिय रहता है।

दूसरी ओर, 'इरादा' एक सचेत अवस्था है जिसमें मानसिक क्षमताओं को सक्रिय किया जाता है और एक कल्पित लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से कार्रवाई के लिए बुलाया जाता है।

इसका अर्थ है किसी व्यक्ति के आचरण को इस प्रकार आकार देना कि वह किसी निश्चित घटना को घटित कर सके। इसलिए, 'इरादे' के मामले में मानसिक क्षमताओं को एक निर्धारित दिशा में प्रक्षेपित किया जाता है। जरूरी नहीं कि इरादे में पूर्वचिन्तन शामिल हो। ऐसी कोई मंशा है या नहीं, यह तथ्य का प्रश्न है। खंड तीसरे में "प्रताड़ित करने का इरादा" शब्द महत्वपूर्ण हैं। जैसा कि पहले ही उल्लेख किया गया है, जब कोई व्यक्ति कोई कार्य करता है, तो यह माना जाता है कि उससे प्राकृतिक परिणामों की अपेक्षा होगी। लेकिन मात्र इस तथ्य से कि कारित हुई चोट प्रकृति के सामान्य क्रम में मृत्यु कारित करने के लिए पर्याप्त है, यह आवश्यक अर्थ नहीं है कि अपराधी उस प्रकृति की चोट कारित करने का इरादा रखता है।

हालाँकि, यह माना लगाया जाता है कि उसका इरादा उस विशेष चोट का कारण बनना था।

ऐसी स्थिति में अदालत को यह सुनिश्चित करना होगा कि क्या मामले में तथ्य और परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो अनुमान का खंडन कर सकें और ऐसे तथ्यों और परिस्थितियों को एक अमूर्त नियम में नहीं रखा जा सकता है और वे हर मामले में अलग-अलग होंगे।

हालाँकि, जैसा कि विरसा सिंह के मामले उपर में बताया गया है, इस्तेमाल किया गया हथियार, उसे चलाने में छोड़े गए बल की डिग्री, पक्षों

के पूर्ववर्ती संबंध, हमला करने का तरीका यानी अचानक या पूर्व-निर्धारित, चोट संघर्ष या हाथापाई के दौरान लगी थी, लगी चोटों की संख्या और उनकी प्रकृति और शरीर का वह हिस्सा जहां चोट लगी थी, कुछ प्रासंगिक कारक हैं।

किसी मामले में उत्पन्न होने वाले इन और अन्य कारकों पर विचार किया जाना चाहिए और यदि इन परिस्थितियों की समग्रता पर अपराध की प्रकृति के बारे में संदेह उत्पन्न होता है, तो लाभ आरोपी को जाना होगा।

कुछ मामलों में, अभियुक्त द्वारा निजी बचाव के अधिकार का प्रयोग जैसे स्पष्टीकरण हो सकते हैं या परिस्थितियाँ भी इसका संकेत दे सकती हैं।

इसी तरह कुछ मामलों में ऐसी परिस्थितियाँ हो सकती हैं जो पहले अपवाद को आकर्षित करती हैं। ऐसे मामलों में अलग-अलग विचार उठते हैं और अदालत को यह तय करना होता है कि क्या अभियुक्त अपवाद के लाभ का हकदार है, हालांकि अभियोजन पक्ष ने स्थापित किया कि धारा 300 आईपीसी के एक या अन्य खंड आकर्षित होते हैं।

वर्तमान जांच में हमें उस पहलू पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम केवल आईपीसी की धारा 300 के खंड तीसरे के दायरे से संबंध हैं।"

[जोर दिया गया] जय प्रकाश उपर के मामले में, चाहत खान बनाम हरियाणा राज्य, (1972) 3 एससीसी 408, चमरू बुधवा बनाम मध्य प्रदेश राज्य, एआईआर 1954 एससी 65] विली (विलियम) स्लेनी बनाम स्टेट ऑफ एमपी, (1955) 2 एससीआर 1140 और हरजिंदर सिंह (उर्फ जिंदा) बनाम दिल्ली प्रशासन, (1968) 2 एससीआर 246 के मामलों में इस न्यायालय के फैसलों का जिक्र करने के बाद न्यायालय ने पृष्ठ 44 पर इस प्रकार कहा: "इन इन सभी मामलों में दृष्टिकोण यह पता लगाने का रहा है कि क्या घटक अर्थात् विशेष चोट पहुंचाने का इरादा मौजूद था या नहीं और यह माना गया है कि किसी लड़ाई में अचानक झगड़ा होने या जब मृतक ऐसी लड़ाई में हस्तक्षेप करता है, तो इरादे के तत्व के बारे में संदेह पैदा होता है क्योंकि ऐसी परिस्थितियों में यह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है कि आरोपी ने शरीर के किसी विशेष हिस्से पर हमला करने का लक्ष्य रखा था।

जब कोई अभियुक्त किसी घातक हथियार से हमला करता है तो यह माना जाता है कि वह कारित चोट पहुंचाने का इरादा रखता है, लेकिन जैसा कि ऊपर बताया गया है, ऐसी परिस्थितियां भी हो सकती हैं, जो इस तरह के अनुमान का खंडन करती हैं और खंड तीसरे के आकर्षण के बारे में संदेह पैदा करती हैं। बेशक बहुत कुछ प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

फिर से जय प्रकाश उपर के मामले में, न्यायालय ने कुलवंत राय बनाम पंजाब राज्य, (1981) 4 एससीसी 245, रणधीर सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1981) एससीसी 484, गुरमेल सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1982) 3 एससीसी 185, जगतार सिंह बनाम पंजाब राज्य, (1983) 2 एससीसी 342, थोलन बनाम तमिलनाडु राज्य, (1984) 2 एससीसी 133 और जगरूप सिंह (सुप्रा) के मामलों में इस न्यायालय के निर्णयों का उल्लेख किया और पृष्ठ 46-47 पर इस प्रकार कहा गया है: - "इन सभी मामलों में, एक ही आद्यात से चोट मौत का कारण बनने के लिए प्रकृति के सामान्य क्रम में पर्याप्त पाई गई।

सुप्रीम कोर्ट ने ऊपर उल्लिखित अचानक झगड़े, हाथापाई आदि जैसी परिस्थितियों पर केवल मन की स्थिति का आकलन करने के लिए विचार किया, अर्थात् क्या अभियुक्त के पास उस विशेष चोट का कारण बनने का आवश्यक इरादा था, यानी यह कहना कि वह स्पष्ट रूप से चाहता था कि केवल ऐसी चोट ही परिणाम होना चाहिए.

इन सभी मामलों में यह माना गया कि उस विशेष चोट का कारण बनने का कोई इरादा नहीं था क्योंकि उन परिस्थितियों में, आरोपी को बमुश्किल पता चल सकता था यानी उसे केवल परिणामों की जानकारी थी।

जिन परिस्थितियों में अपीलकर्ता को चोट पहुंचाने का मौका मिला, उससे यह महसूस हुआ या कम से कम यह संदेह पैदा हुआ कि उसकी

सभी मानसिक क्षमताओं को विशेष परिणाम प्राप्त करने का इरादा बनाने के लिए प्रेरित नहीं किया जा सकता था।

हम यह बता सकते हैं कि हमें मौत का कारण बनने के इरादे से कोई सरोकार नहीं है, ऐसी स्थिति में यह सीधे तौर पर हत्या होगी, जब तक कि अपवाद न हो। हम खंड तीसरे के तहत उस विशेष चोट के इरादे से संबंध हैं जो एक व्यक्तिपरक जांच है और जब एक बार ऐसा इरादा स्थापित हो जाता है और यदि इच्छित चोट मौत का कारण बनने के लिए प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में उद्देश्यपूर्ण रूप से पर्याप्त पाई जाती है, तो खंड तीसरा आकर्षित होता है और यह हत्या होगी जब तक कि धारा 300 के अपवादों में से एक को आकर्षित नहीं किया जाता है।

दूसरी ओर, यदि 'इरादे' का यह घटक स्थापित नहीं होता है या यदि इस संबंध में कोई उचित संदेह उत्पन्न होता है, तो केवल यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि खंड तीन आकर्षित नहीं होता है और आरोपी को चोट पहुंचाने के ज्ञान का श्रेय दिया जाना चाहिए उससे मौत होने की संभावना थी, ऐसी स्थिति में आईपीसी की धारा 304 भाग II के तहत यह गैर इरादतन हत्या होगी।

कर्नाटक राज्य बनाम वेदनायगम, (1995) 1 एससीसी 326 के मामले में, आरोपी ने छाती पर एक ही चाकू से वार किया, जिसके परिणामस्वरूप तत्काल मृत्यु हो गई और विचारण न्यायालय ने उसे धारा

302 के तहत दोषी ठहराया, लेकिन अपील को प्राथमिकता दिए जाने पर, उच्च न्यायालय ने कर्नाटक ने इसे धारा 304 भाग II के तहत एक में बदल दिया।

जब मामला इस अदालत में लाया गया, तो धारा 302 के तहत आरोपी को दोषी ठहराने वाले विचारण न्यायालय के फैसले को यह कहते हुए बहाल कर दिया गया कि "इसमें कोई संदेह नहीं है कि आरोपी ने छाती पर विशेष चोट पहुंचाने का इरादा किया था, जो जरूरी तौर पर घातक साबित हुआ।

इसलिए, आईपीसी की धारा 300 का खंड तीसरा स्पष्ट रूप से आकर्षित होता है।

महेश बाल्मीकि उर्फ मुन्ना बनाम मध्य प्रदेश राज्य, 2000 (1) एससीसी 319 के मामले में, आरोपी ने 6वीं और 7वीं पसलियों के कोस्टल जोड़ के बीच उरोस्थि के बाईं ओर छाती पर चाकू से एक ही घातक वार किया। दोनों पसलियों में फ्रैक्चर और घाव का ट्रैक पसलियों से गुजरने के बाद उरोस्थि, पेरीकार्डियम, पूर्वकाल और पीछे से होकर गुजरता है और उसके बाद यकृत में प्रवेश करता है और पेट के एक हिस्से में छेद कर देता है।

वहां, दंड संहिता की धारा 302 के तहत दोषसिद्धि को उच्च न्यायालय द्वारा बरकरार रखा गया था और जब विशेष अनुमति द्वारा

इस न्यायालय में अपील लाई गई, तो धारा 302 के तहत दोषसिद्धि की पुष्टि करते हुए, इस न्यायालय ने पृष्ठ 322-323 पर इस प्रकार टिप्पणी की: -

> "एक आद्यात के विवाद को ध्यान में रखते हुए, यह बताया जा सकता है कि ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है कि एक आद्यात के सभी मामलों में आईपीसी की धारा 302 लागू नहीं होती है।
>
> एक भी झटका, कुछ मामलों में, धारा 302 आईपीसी के तहत, कुछ मामलों में धारा 304 आईपीसी के तहत और कुछ अन्य मामलों में धारा 326 आईपीसी के तहत सजा दिला सकता है।
>
> अपराध की प्रकृति के संबंध में प्रश्न प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्धारित किया जाना चाहिए।
>
> चोट की प्रकृति, चाहे वह शरीर के महत्वपूर्ण या गैर-महत्वपूर्ण हिस्से पर हो, इस्तेमाल किया गया हथियार, जिन परिस्थितियों में चोट लगी है और जिस तरीके से चोट पहुंचाई गई है, वे सभी प्रासंगिक कारक हैं जो अपराधी और

उसके द्वारा किए गए अपराध के आवश्यक इरादे या जानकारी का निर्धारण करें।"

उपरोक्त सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए, यदि हम वर्तमान मामले के तथ्यों की जांच करते हैं, तो धारा 300 का खंड तीसरा पूरी तरह से आकर्षित होता है।

ऐसा प्रतीत होता है कि आरोपी व्यक्ति घातक हथियारों से लैस होकर आए थे और विवाद हुआ और गर्म शब्दों का आदान-प्रदान हुआ, जिसके बाद अपीलकर्ता नंबर 1 ने पीड़िता राम पतिया देवी पर भाला से हमला किया, जिससे छाती पर चोट लगी, महत्वपूर्ण रक्त वाहिकाएं फट गईं और महाधमनी और अन्य धमनियां कट गईं। जिसके परिणामस्वरूप उसकी तत्काल मृत्यु हो गई।

इस स्तर पर, राम पतिया देवी पर चोट का उल्लेख करना उपयोगी होगा जैसा कि डॉक्टर द्वारा पाया गया था, जिन्होंने उनके शव का पोस्टमार्टम किया था, जो इस प्रकार है:

"एक मर्मज्ञ घाव 2" x 1" x 4" गहरा [एल] छाती के शीर्ष पर, [एल] हंसली के ठीक नीचे, काटने, त्वचा, मांसपेशियों और महत्वपूर्ण रक्त वाहिकाओं, जैसे। महाधमनी का क्षेत्र. शरीर पर छाती पर, दाग के पीछे महाधमनी के आर्क और सबक्लेवियन धमनी के कटने का निशान पाया गया, जिसके

परिणामस्वरूप अत्यधिक रक्तस्राव हुआ। गंभीर प्रकृति का, तेज धार वाले नुकीले हथियार से उत्पन्न होना। 12 घंटे के अंदर. मेरी राय में, मृत्यु गंभीर रक्तस्राव के परिणामस्वरूप हृदय श्वसन विफलता और बड़ी नसों के टूटने के कारण सदमे के कारण हुई, जैसा कि ऊपर बताया गया है।"

चोट की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, जिसमें महत्वपूर्ण रक्त वाहिकाएं फट गईं, अधिकांश महाधमनी और धमनियां कट गईं और जब डॉक्टर ने राय दी कि मौत गंभीर रक्तस्राव और महान नसों के टूटने के कारण सदमे के परिणामस्वरूप हुई, तो निस्संदेह, यह उचित हो सकता है। इससे यह अनुमान लगाया गया कि मृतक को पहुंचाई गई ऐसी अकेली चोट प्रकृति की सामान्य प्रक्रिया में मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी।

उपरोक्त परिस्थिति से पता चलता है कि आरोपी ने जानबूझकर चोट पहुंचाई है और वही अपीलकर्ता धूपा चमार की मानसिक स्थिति को इंगित करेगा कि उसने घातक हथियार से निशाना बनाकर चोट पहुंचाई।

यह दिखाने के लिए साक्ष्य या उचित स्पष्टीकरण के अभाव में कि इस अपीलकर्ता का इरादा महत्वपूर्ण रक्त वाहिका को तोड़ने और महाधमनी और अन्य धमनियों को काटने के लिए पर्याप्त बल के साथ छाती में भाला द्वारा चोट पहुंचाने का नहीं था, यह निष्कर्ष निकालना

विकृत होगा कि उसका इरादा वह चोट पहुँचाने का नहीं था जो उसने कारित की।

जब एक बार घटक 'इरादा' स्थापित हो जाता है तो अपराध हत्या होगा क्योंकि इच्छित चोट प्रकृति के सामान्य क्रम में मौत का कारण बनने के लिए पर्याप्त थी।

इसलिए, अपरिहार्य निष्कर्ष यह होगा कि अपीलकर्ता नंबर 1- धूपा चमार ने हत्या का अपराध किया है, न कि गैर इरादतन हत्या का इस स्थिति में, हमें नहीं लगता कि उच्च न्यायालय ने दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपीलकर्ता नंबर 1-धूपा चमार की दोषसिद्धि को बरकरार रखने में कोई त्रुटि की है।

अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने आगे कहा कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि सात आरोपियों में से, विचारण न्यायालय ने स्वयं तीन आरोपियों, स्वामीनाथ चमार, राजबली चमार और राम होशियार चमार को धारा 302/149 के तहत आरोप से बरी कर दिया। दंड संहिता के तहत, अपीलकर्ता संख्या 3-डोमा चमार और अपीलकर्ता संख्या 4-अदालत चमार को दंड संहिता की धारा 302/149 के तहत दोषी ठहराना उचित नहीं था और उच्च न्यायालय द्वारा भी इसे बरकरार रखना उचित नहीं था।

यह भी प्रस्तुत किया गया है कि जहां तक अपीलकर्ता नंबर 2-तोखा चमार का संबंध है, उच्च न्यायालय ने उसकी दोषसिद्धि को दर्ज करने के बाद दंड संहिता की धारा 302 के तहत उसकी दोषसिद्धि को धारा 302/149 के तहत परिवर्तित करना यह निष्कर्ष देने के बाद काफी अनुचित था। धारा 302 के तहत सरलीकरण अनुचित था क्योंकि चिकित्सीय साक्ष्यों के अनुसार पीड़ित धरम चमार पर पाई गई चोटें न तो मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं और न ही मृत्यु का कारण बनने की संभावना थी, यह सामान्य था और टॉक्सिमिया के परिणामस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई।

हमारी राय है कि इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उपरोक्त सात आरोपियों में से तीन आरोपियों को ट्रायल कोर्ट ने धारा 302/149 के तहत आरोप से बरी कर दिया था और किसी अन्य व्यक्ति के शामिल होने की बात नहीं कही गई है। जैसा कि अभियोजन मामले और साक्ष्य में उल्लिखित है, और चूंकि आरोपी व्यक्तियों की संख्या पांच से कम हो जाती है, इसलिए किसी भी गैरकानूनी सभा की मौजूदगी नहीं कही जा सकती है, क्योंकि धारा 302/149 के तहत अपीलकर्ता नंबर 2 से 4 की सजा अनुचित हो जाती है।

इन अपीलकर्ताओं को अन्य धाराओं के तहत दोषी ठहराए जाने के संबंध में, उनकी ओर से उपस्थित विद्वान वकील कोई कमजोरी नहीं बता सके।

हालाँकि, उन्होंने प्रस्तुत किया कि इन धाराओं के तहत, दी गई अधिकतम सज़ा एक वर्ष है और चूँकि उन्होंने इससे अधिक सजा काट ली है, इसलिए उन्हें तुरंत रिहा करने का निर्देश दिया जाना चाहिए।

हम इस निवेदन में बल पाते हैं क्योंकि यह बताया गया है कि टोखा चमार-अपीलकर्ता नंबर 2 सात साल की अवधि तक जेल में रहा है और अपीलकर्ता नंबर 3-डोमा चमार और अपीलकर्ता नंबर 4- अदालत चमार में से प्रत्येक दो साल तीन महीने.

परिणामस्वरूप, अपीलकर्ता नंबर 1-धूपा चमार की अपील विफल हो जाती है और तदनुसार इसे खारिज कर दिया जाता है। अपीलकर्ता संख्या 2-तोखा चमार, अपीलकर्ता संख्या 3-डोमा चमार और अपीलकर्ता संख्या 4-अदालत चमार की अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है, दंड संहिता की धारा 302/149 के तहत उनकी दोषसिद्धि और सजा को रद्द कर दिया जाता है और उन्हें इस आरोप से बरी कर दिया जाता है।

अन्य धाराओं के तहत उनकी दोषसिद्धि और सजा की पुष्टि की गई है, लेकिन चूंकि वे पहले ही इसके तहत दी गई सजा काट चुके हैं, इसलिए उन्हें निर्देश दिया जाता है कि यदि किसी अन्य मामले में आवश्यक न हो तो उन्हें तुरंत रिहा किया जाए।

अपील खारिज/आंशिक रूप से अनुमत।

एस के एस.

यह अनुवाद आर्टिफिशल इंटेलिजेन्स टूल सुवास की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी मानेन्द्र सिंह (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए , निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा |